

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 1945 / 2016 / बीकानेर

मैसर्स हरीश जनरल स्टोर, स्टोशन रोड, बीकानेर.अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-बी, बीकानेर.प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या 1946 / 2016 / बीकानेर

मैसर्स सर्वोत्तम, नापासर, बीकानेर.अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-तृतीय, वृत्त-ए, बीकानेर.प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या 1950 / 2016 / बीकानेर

मैसर्स पायोनियर ट्रेडिंग कम्पनी, गंगाशहर रोड, बीकानेर.अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत्त-बी, बीकानेर.प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दोसाया, अभिभाषक.

.....अपीलार्थीगण की ओर से

श्री रामकिशोर खदाव, उपराजकीय अभिभाषक.

.....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 25 / 09 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा क्रमशः अपील संख्या 313, 308 एवं 381 / आरवैट / बीकानेर / 2014-15 में पारित पृथक-पृथक पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय / तृतीय, वृत्त-बी / ए, बीकानेर (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेशों के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 / 24 सपठित नियम 19ए के तहत विलम्ब शुल्क को यथावत् रखा गया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि व्यवसायीगण द्वारा उनके आलौच्य अवधि की वार्षिक वैट-11 को ऑनलाईन भरकर उनकी हार्ड कॉपी विभाग में देरी से जमा करवायी। इस कारण कर निर्धारण अधिकारी ने वार्षिक रिटर्न वैट-11 प्रस्तुत करने की पावती हार्ड कॉपी देरी से प्रस्तुत किये जाने के कारण नियम 19ए में निम्न तालिकानुसार लेट फीस राशि रूपये का आरोपण करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश को यथावत् रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर.....2

3. प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश दिनांक	कर निर्धारण आदेश		विलम्ब शुल्क
1.	1945/2016	28.12.2015	2012-13	09.06.2014	5,000
2.	1946/2016	03.02.2016	2012-13	21.02.2014	3,200
3.	1950/2016	28.12.2015	2011-12	18.04.2014	5,000

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारीगण की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि व्यवसायीगण द्वारा आलौच्य अवधि का विवरण पत्र ऑनलाईन रूप से समय पर प्रस्तुत कर दिया गया था। परन्तु नियम 19ए में यह निर्धारित नहीं किये जाने के कारण कि "विभाग में रिटर्न की हार्ड कॉपी लेट जमा करवाने पर लेट फीस का आरोपण किया जा सकता है" इस कारण हार्ड कॉपी जमा करवाने में देरी हो गई। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से लेट फीस का आरोपण कर दिया। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवसायीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही कर निर्धारण आदेश पारित कर दिये, जो न्यायहित में अविधिक आदेश थे। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवसायीगण द्वारा ऑनलाईन रिटर्न तो समय पर भर दिया, परन्तु उसकी हार्ड कॉपी विभाग में देरी से जमा करवायी गई। जिसे विभाग द्वारा रिटर्न को देरी से जमा मानते हुए विधिक रूप से कार्यवाही करते हुए लेट फीस का आरोपण किया गया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायीगण द्वारा उनकी आलौच्य अवधि का ऑनलाईन रिटर्न तो समय पर भर दिया, परन्तु उसकी हार्ड कॉपी विभाग में देरी से जमा करवायी गई। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिटर्न को देरी से जमा मानते हुए लेट फीस का आरोपण कर दिया गया।

7. विवरण प्रस्तुत करने के संदर्भ में सर्वप्रथम विधिक धारा 21, नियम 19 व नियम 19ए का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा जो कि निम्न प्रकार है :-

Sec. 21. FILING OF RETURN - (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner. (2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall

निरन्तर.....3

Purnish return for such period in such from and mannêr and within such time as may be spci iied. (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest SO to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns of may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.

राज्य सरकार के नियम 19 में दिनांक 09.03.2011 को संशोधन कर निम्न प्रावधान किये गये :-

19(1) Returns - (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT 10, VAT 10A and VAT 11 as the case may be,

(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web site of the department, unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official website of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, within fifteen days of the last date for filing of such return(s), failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s)"

(3) Where the amount of tax, interest or late fee, if not paid electronically, the dealer shall furnish the copy of ehallan in Form VAT-37, receipt in Form VAT-38 or certificate of tax deduction at source, as a proof of deposit, to the assessing authority or the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, within fifteen days of the last date for filing or such returns (s),

(4) Return in Form VAT I shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers: (a) who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3: or (h) who exclusivey deals in goods; (1) which are exempted under the Act; or (ii) on which option to pay tax in lump sum has been exercised under section 5, or (iii) which are taxable at first point in the series of sales and the goods have suffered tax at the said -first poin; or (iv) which are taxable at maximum retail price under sub-section (7) of section 4 and such goods have suffered lax at maximum retail price under the said sub-section; or (v) which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee; or (vi) as may be notified by the Commissioner.

(5) Return in Form VAT- 10 shall he submitted by all dealers other than those enumerated in sub-rule (4) above, along with statement of purchase in Form VAT07A and statement of sales in Form VAT-08A,

(a) within sixty days of the end of the quarter by the dealers who have depsited less than Rs. 50,000/- as tax under the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 including the Central Sales Tax Act, 1956, during the previous year.

(b) within forty five days of the end of the quarter by the dealers other than enumerated in clause (a) above.

Explanation Quarter menas the period of three months ending on 30th June, 30lli September, 31 December and 31 March and month shall mean calendar month.

(6) Annual Return in Form VAT shall be submitted by all dealers covered under subrule(5) within [ten month] from the end of the relevant year.

(7) Where a dealer has more than one place of business, he shall include in the return, the turnover of the principal place of business as well as the turnover of all other places of business. (8) Where a dealer discovers any omission or error in [Form VAT - 10 or Form VAT WA or Form VAT- i 1] furnished by him, he may furnish revised return at any time prior to the due date of filing annual return or audit report or on receipt of the notice under subsection (1) of section 24, whichever is earlier.

(9) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) to (7) above, the return(s) for the period prior to 01-04-2011 may be submitted in such manner and in such form which was in force for that period [(10) Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shal be submitted along

निरन्तर.....4

with proof of deposit of dut tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted. it shall be deemed to be case of non-filing of the return.

8. अपीलार्थी व्यवहारीगण ने विचाराधीन प्रकरणों में विहित तरीके से विहित समय में विवरणियों को प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके कारण विवरणियों हेतु नियम 19ए(iii) के तहत विलम्ब शुल्क का आरोपण करने के बाद उनकी Acknowledgement receipt कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है, चूंकि विलम्ब शुल्क शास्ति नहीं है बल्कि विवरणियों के विलम्ब से प्रस्तुत करने पर शुल्क का निर्धारण है, जिसके लिये नोटिस दिये जाना अपेक्षित नहीं है। उक्त राशि विलम्ब होने पर अपीलार्थीगण को स्वयं ही विवरणियों के साथ जमा करवाना चाहिये था। नियम 19 एवं 19ए के संबंधित उपबंध इस प्रकार से थे :-

"The Rule 19 (2) as existed on 01.04.2011, was as under: "(2) Every dealer shall submit return electronically through the official web-site of the department unless otherwise notified by the Commissioner. The return shall be digitally signed by the dealer or his business manager and in case it is not digitally signed, the dealer shall furnish, the acknowledgement generated through Official Web-Site of the Department and shall be verified by himself or his business manager by affixing his signature on it, '[within fifteen days of the last date offihing of such return(s)], failure to do so shall be deemed to be a case of non filing of returns(s) filing"

For the period 01.04.2011 to 31.03.2012 (as substituted by the amendment dated 09.03.2011 w. e.f 01. 04.2011) "19A Late fee. - Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of (i) rupees one hundred per day for a period of first fifteen days and rupees five hundred per day thereafter, subject to a maximum of rupees fifty thousand or thirty percent of the tax assessed whichever is lower, in case he is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."

9. इस प्रकार विचाराधीन प्रकरणों में अपीलार्थीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बताया कि यदि इन प्रकरणों में हमारी रिटर्न Non Filing of Return की श्रेणी में मानी जाती है तो माननीय कर बोर्ड के वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसार उस पर कोई लेट फीस देय नहीं होती है, परन्तु रेकार्ड से स्पष्ट है कि व्यवहारीगण ने या तो रिटर्न देशी से प्रस्तुत की है तथा रिटर्न प्रस्तुत करने के प्रमाण स्वरूप Acknowledgement की प्रति नियत अवधि में संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार इसे Non-filing of return नहीं कह सकते। इसी प्रकार कर बोर्ड के एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.07.2018 अपील संख्या 2251/2015/बीकानेर के निर्णय की वृहदपीठ द्वारा पुष्टि की गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय मैसर्स सुनील बनाम कर निर्धारण अधिकारी अपील संख्या 1063/2015/टॉक में दिये गये निर्णय दिनांक 07.03.2018 के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा नियम 19A के तहत आरोपित विलम्ब शुल्क यथावत् रखा जाता है।

9. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों को यथावत् रखा जाता है एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदनलाल मालवीय)
सदस्य